

एससी का जनसंख्या नियंत्रण याचिका पर सुनवाई से इनकार

3

गुजरात में बीजेपी ने दी है दंगा मुक्त और सुशासन युक्त सरकार : अनुराग ठाकुर

8

देश की उन्नति महिलाओं के विकास से मापा जा सकता है : राज्यपाल

अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 18 नवम्बर । सिक्किम विश्वविद्यालय का छठवां दीक्षांत समारोह आज शुक्रवार को मनन केंद्र में आयोजित किया गया। राज्यपाल गंगा प्रसाद ने आज सिक्किम विश्वविद्यालय के छठवां दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि तथा विश्वविद्यालय के मुख्य कुलाधिपति के रूप में उपस्थित रहे। राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में विभिन्न उपाधि प्राप्त करने वाले

विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यहाँ से आत्मसात किया ज्ञान और जीवन मूल्य सदा आपका मार्गदर्शन करे और जीवन को प्रकाशित करे। इस साल सिक्किम विश्वविद्यालय ने सहाय्यपी छठवां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है। जानकारी अनुसार इसके अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में 12661 छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पीजी,

एमफिल तथा पीएचडी में सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक एवं रजत पदक से भी नवाजा गया। समारोह में बड़ी संख्या में युवतियों को उपाधियाँ हासिल करते देख राज्यपाल गंगा प्रसाद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज भारत के सभी क्षेत्र जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक,

अनुसंधान, साहित्य, खेल कूद, सैन्य आदि में महिलाएं अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, पूरा समाज शिक्षित होता है। देश का विकास महिलाओं के विकास से मापा जा सकता है। नशाखोरी एवं दुर्व्यसनों के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि नशा और दवाओं का दुरुपयोग समाज और देश को खोखला बना देती है। इस दिशा में उन्होंने सभी

से आह्वान किया कि राज्य, देश और शिक्षा संस्थानों सभी मिलकर आगे आये और इस समस्या को मिलकर समाधान करें और नशा मुक्त सिक्किम, नशा मुक्त भारत का निर्माण कर देश की भावी पीढ़ी को सशक्त बनाये ताकि आगे जाकर वे देश पर बोझ नहीं देश को अपना नेतृत्व प्रदान कर सकें। राज्य में केसर खेती के सफल परिणाम को देखते हुए राज्यपाल ने सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय के

वनस्पति विज्ञान विभाग एवं कुलपति अविनाश खरे को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत खुशी की बात है कि सिक्किम में जैविक केसर उत्पादन के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। यह अपने आप में एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इसकी गुणवत्ता कश्मीर से भी अच्छी है। केसर खेती के उत्पादन से राजस्व बढ़ेगा साथ ही रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। इस क्षेत्र में सभी से आगे आकर केसर के और अधिक



उत्पादन में सहयोग करने का आह्वान किया। आग्रह किया कि डिजिटल और व्यवसायिक युग में अपनी योग्यता विद्यार्थियों से राज्यपाल ने का उपयोग (शेष पृष्ठ ०३ पर)

सिक्किम एसएसीएस द्वारा रेड रिबन क्वीज प्रतियोगिता आयोजित



अनुगामिनी का.सं.
गंगटोक, 18 नवम्बर । सिक्किम के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग के तहत सिक्किम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी (एसएसीएस) द्वारा आज स्थानीय सिक्किम प्रोफेशनल नर्सिंग कॉलेज में आयोजित तीसरे राज्यस्तरीय रेड रिबन क्वीज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का खिताब लिंगमू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने जीता जो अब दिसम्बर में नागालैंड में आयोजित होने वाली क्षेत्रीय रेड रिबन क्वीज प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं प्रतियोगिता में दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः सोनम चोडा लेप्चा मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल और सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज बुर्तुक ने प्राप्त किया। आज इस कार्यक्रम में सिक्किम एसएसीएस के प्रधान मुख्य सलाहकार सह परियोजना निदेशक डॉ. ज्ञानेंद्र सिन्चुरी मुख्य अतिथि और प्रोफेशनल नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल हिशे ल्हामू कालेयोन

लिंगमू गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनी विजेता
सम्माननीय अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। वहीं इस दौरान आईईसी की सहायक निदेशक लुवाना राई एवं सहायक युवा निदेशक फूल छिरिंग लेप्चा के अलावा सोसाइटी के फेकल्टी, छात्र तथा प्रतिभागीगण भी शामिल रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राज्य एड्स नियंत्रण समितियों द्वारा एचआईवी एड्स, किशोर स्वास्थ्य, मानसिक एवं अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दों से सम्बंधित सूचनाओं के प्रसार हेतु युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना था। वर्ष 2019 में शुरू हुई यह प्रतियोगिता केवल रेड रिबन वाले क्लबों के लिए ही है। सिक्किम एसएसीएस द्वारा इस वर्ष 5 नवम्बर को प्रतियोगिता का एक ऑनलाइन प्रारंभिक दौर आयोजित किया गया जिसमें 57 (शेष पृष्ठ ०३ पर)

स्वस्थ समाज एवं मादक रोकथाम हेतु सारथी 1.0 की हुई शुरुआत



अनुगामिनी का.सं.
पाकिम, 18 नवम्बर । स्वस्थ व स्वच्छ समाज के निर्माण की दिशा में स्कूलों एवं समाज में मादक पदार्थों की रोकथाम तथा मानसिक चिकित्सा सुनिश्चित करने हेतु रेनॉक के विधायक विष्णु खतिवाड़ा ने आज पाकिम कम्युनिटी हॉल में टाइटेन कम्पनी के सहयोग से सारथी 1.0 पहल की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार सह कार्यक्रम के मुख्य रिसोर्स पर्सन रोहित राज महाराज के अलावा सारथी अध्यक्ष सोनम चोफेल शेरपा और टाइटेन कम्पनी की ओर से श्री

बोहरा उपस्थित थे। गौरतलब है कि सारथी को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिले में मार्च 2023 तक पांच महीनों के लिए लागू किया जायेगा जिसमें 12 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के अलावा 30 आशाओं को कवर किया जायेगा। आज इस अवसर पर सारथी अध्यक्ष हरिराम रिजाल ने संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए सारथी 1.0 की शुरुआत के बारे पर जानकारी दी। वहीं मुख्य रिसोर्स पर्सन सह सीएम सलाहकार रोहित राज महाराज (शेष पृष्ठ ०३ पर)

नागर विमानन मंत्रालय
भारत सरकार

75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

ईटानगर में प्रथम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ अरुणाचल प्रदेश को मिला विकास का नया प्रवेशद्वार

“ हम अरुणाचल को पूर्वी एशिया का एक मुख्य प्रवेशद्वार बनाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। अरुणाचल की सामरिक भूमिका को देखते हुए राज्य में आधुनिक अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। ”
नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर का उद्घाटन

परियोजना के मुख्य लाभ

- अरुणाचल प्रदेश की राजधानी के लिए सीधा हवाई संपर्क
- प्राकृतिक आपदा और चिकित्सीय आपात स्थिति में क्षेत्र के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों तक सुगम पहुंच
- क्षेत्र में पर्यटन उद्योग एवं आजीविका सृजन के अवसरों को प्रोत्साहन
- स्थानीय उपज एवं उत्पादों के निर्यात एवं व्यापार हेतु अवसरों में वृद्धि

हवाई अड्डे की मुख्य विशेषताएं

- एयरबस-320 प्रकार के विमानों के प्रचालन के लिए उपयुक्त
- चार एमआई-17 प्रकार के हेलीकॉप्टर की पार्किंग के लिए पृथक एग्रन
- 24x7 प्रचालनों की सुविधा के लिए इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम से सुसज्जित
- व्यस्ततम समय में 300 यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम टर्मिनल भवन

नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री द्वारा

गरिमामयी उपस्थिति

ब्रिगेडियर (डॉ.) बी. डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त)
राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश

पेमा खांडू मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश	किरेन रीजीजू केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री	चौना मेईन उप-मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश	नबाम रेबिया संसद सदस्य
---	--	---	---------------------------

Donyi Polo Jaaj Jarku Ryang, Itanagar डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर Donyi Polo Airport, Itanagar

शनिवार, 19 नवम्बर, 2022 | प्रातः 09:30 बजे | डोनी पोलो हवाई अड्डा, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

डीडी न्यूज़ पर सीधा प्रसारण

जूवेनाइल जस्टिस एक्ट पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 के बहुचर्चित कटुआ गैंगरेप और मर्डर केस में नाबालिग बताए गए एक आरोपी के बारे में यह व्यवस्था दी कि वह अपराध को अंजाम देते वक्त बालिग था और इसीलिए उसके खिलाफ एक वयस्क के रूप में ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह मामला आठ साल की एक बच्ची के साथ क्रूरता की इंतिहा के चलते ही नहीं, आरोपियों के बचाव में शुरू की गई राजनीतिक मुहिम के कारण भी देश भर में चर्चित हुआ था। मगर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले की अहमियत के कई और पहलू भी हैं। इस आरोपी की सही उम्र को लेकर संदेह शुरू से था। बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में जो दस्तावेज पेश किए गए थे, उनमें भी खामियां पाई गईं। मगर निचली अदालतों में ये खामियां नहीं पकड़ी जा सकीं।

सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं खामियों को मद्देनजर रखते हुए विशेषज्ञों की समिति की उस रिपोर्ट पर भरोसा करना बेहतर समझा, जिसमें अपराध के समय आरोपी की उम्र 19 से 23 साल के बीच होने की बात कही गई है। हालांकि कोर्ट ने भी माना कि विशेषज्ञों की ऐसी मेडिकल ओपिनियन कोई ठोस साक्ष्य नहीं बल्कि एक राय ही है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ऐसे गंभीर अपराधों के मामले में अगर आरोपी की उम्र को लेकर संदेह की स्थिति बनती हो तो अपर्याप्त दस्तावेज के बजाय इस राय को ही फैसले का आधार बनाया जाना चाहिए। फैसले का दूसरा अहम पहलू अपराधियों को नाबालिग मान कर उन्हें दी जाने वाली कानूनी रियायतों से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का यह ऑब्जर्वेशन बेहद महत्वपूर्ण है कि नाबालिग बताकर अपराधियों को सजा में रियायतें दिए जाने से उनमें सुधार होने के बजाय अपराधियों का दुस्साहस ही बढ़ता है।

साफ है कि कोर्ट का इशारा जूवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 की ओर था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के औचित्य पर कोई सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह कहते हुए इस पर सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि नाबालिगों द्वारा अपराध के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हम यह सोचने को मजबूर हैं कि क्या सचमुच यह कानून अपना मकसद पूरा करने में कामयाब हुआ है। साफ है कि अब आगे का काम सरकार का है।

निश्चित रूप से कच्ची उम्र में किए गए अपराधों के लिए सजा देते हुए ध्यान बच्चों के सुधार पर ही होना चाहिए, लेकिन कोई खास प्रावधान उन बच्चों में सुधार ला रहा है या नहीं, यह देखना भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा होना चाहिए। खासकर जब ऐसे संकेत मिल रहे हों कि घृणित कृत्यों को अंजाम देने के बाद अपराधी तत्व उस प्रावधान का इस्तेमाल अपनी सजा कम करवाने में कर रहे हैं, तो फिर उसकी अनदेखी करने का कोई कारण नहीं रह जाता। सरकार को तत्काल इस दृष्टि से जूवेनाइल जस्टिस एक्ट पर पुनर्विचार की दिशा में प्रयास शुरू कर देने चाहिए।

चीन का नया मोहरा है तुर्किये

रवीन्द्र दुबे

वैश्विक परिदृश्य पर क्या चीन अपने धनबल का प्रयोग कर भारत को राजनयिक दृष्टि से अलग-थलग करने की कोशिशों में लगा हुआ है ? यह प्रश्न फिलहाल राजनयिक गलियारों में बड़ी तेजी से घूम रहा है। जानकार सूत्रों के अनुसार, चीन के साथ भारत का सीमा संघर्ष पश्चिम एशिया में दो एशियाई शक्तियों के बीच व्यापक टकराव में फैल रहा है। मसलन, पश्चिम एशिया की एक और क्षेत्रीय शक्ति और खास क्षेत्रीय खिलाड़ी तुर्किये के साथ भारत के संबंध कश्मीर पर पाकिस्तान का पक्ष लेने के कारण खराब हो गए हैं।

कश्मीर में भारत विरोधी प्रभाव अभियानों को बढ़ावा देने में एक और दुबई बनने के बाद तुर्किये जल्द ही भारतीय रणनीतिकारों के लिए एक और सिरदर्द पैदा कर सकता है। कश्मीर पर एक-दूसरे के साथ मतभेद होने के अलावा, तुर्किये और भारत अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच संघर्ष में विपरीत पक्षों का समर्थन कर रहे हैं। तुर्किये और पाकिस्तान विश्व मंच पर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, जैसा कि कश्मीर पर उनके इसी तरह के बयानों से देखा गया है। विदेशमंत्री एस. जयशंकर ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान तुर्किये के राष्ट्रपति अर्दोआन द्वारा कश्मीर पर विचार करने की बात पर पलटवार किया था।

दूसरी ओर हाल ही के महीनों में चीन के साथ तुर्किये के संबंधों में सुधार हुआ है। कोविड-19 महामारी के कारण आसमान छूते बजट घाटे के कारण तुर्किये निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए चीन की ओर रुख कर रहा है। जून में तुर्किये ने 2019 में हस्ताक्षरित एक करोड़ डॉलर मुद्रा

स्वैप व्यवस्था के तहत चीन के केंद्रीय बैंक द्वारा दी गई 40 करोड़ डॉलर की वित्त पोषण सुविधा का उपयोग किया। तुर्किये ट्रांस-यूरेशियन कनेक्टिविटी के लिए बिल्डिंग एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) की महत्वाकांक्षा के एक केंद्रीय घटक के रूप में भी नजर आ रहा है, जो परिवहन, रसद, ऊर्जा और दूरसंचार क्षेत्रों में बड़े चीनी निवेश को आकर्षित कर रहा है।

इसके अलावा चीन अपने शिनजियांग क्षेत्र के मूल निवासी तुर्क मुस्लिम उइगरों के लिए अंकारा के समर्थन को बेअसर करने में सफल रहा है। हाल के महीनों में तुर्किये में उइगर शरणार्थियों ने तुर्किये के अधिकारियों द्वारा बढ़ते उत्पीड़न का सामना करने की सूचना दी है। चीन के साथ भारत के बदलते भू-राजनीतिक समीकरण नई दिल्ली के लिए न केवल हिंद-प्रशांत क्षेत्र में-जिसे एशिया प्रशांत भी कहा जाता है- बल्कि पश्चिम एशिया में भी अमेरिका के साथ अधिक निकटता से गठबंधन करने की आवश्यकता को रखांकित करते हैं। नई दिल्ली को चीन के खिलाफ अपने संघर्ष में इच्छुक क्षेत्रीय भागीदारों को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।

पश्चिम एशिया में भारत की हालिया परेशानियां कम से कम कुछ हद तक पूरे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव से उपजी हैं। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट (एईआई) के चाइना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रैकर के अनुसार 2005 और 2019 के बीच चीन ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका में 5,500 करोड़ डॉलर से अधिक का निवेश किया। एडडेटा रिसर्च लैब के आंकड़ों के अनुसार, 2004 और 2014 के बीच चीन ने

इस क्षेत्र में लगभग 4,280 करोड़ डॉलर की वित्तीय सहायता दी। क्षेत्र के कई देशों के लिए चीन उनका शीर्ष व्यापारिक भागीदार है और प्रौद्योगिकी का एक प्रमुख स्रोत है।

बात सिर्फ तुर्किये तक ही सीमित नहीं है। ईरान पर भी नजर रखना जरूरी है। यह संकेत इस बात से मिलता है कि चीन के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी का ढोल पीटते हुए ईरान ने चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान से जोड़ने वाली एक रेलवे परियोजना में भारत की संभावित भूमिका को स्पष्ट रूप से रद्द कर दिया है। ईरान एक ऐसा क्षेत्रीय खिलाड़ी है, जहां भारत का प्रभाव चीन के पक्ष में घटता नजर आ रहा है। चीन के साथ ईरान की व्यापक रणनीतिक साझेदारी समझौते की खबर जनता के सामने जाहिर होने के कुछ दिनों बाद ही ईरान ने एक रेलवे लिंक के निर्माण की पहल की।

यह लिंक ईरान के चाबहार बंदरगाह को अफगानिस्तान के जेरंज प्रांत से जोड़ती है। इससे भारत को परियोजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाने की बची-खुची उम्मीद भी जाती रही। यहां यह जानना जरूरी है कि भारत ने चाबहार बंदरगाह को रणनीतिक संपत्ति के रूप में पेश किया है, जहां उसने 10 साल की अवधि में 15 करोड़ डॉलर तक का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जो अन्य बातों के अलावा, हिंद-प्रशांत में चीन की 'मोतिवों की माला' को टट्टर देने और ग्वाटर में पाकिस्तान के चीन निर्मित बंदरगाह के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद करेगा। गौरतलब है कि चाबहार बंदरगाह ग्वाटर से महज 200 किलोमीटर की दूरी पर है। तेहरान के इस कदम के वास्तविक कारण को नई दिल्ली में राजनयिक

मनमानी पर उतरी विजयन सरकार

के. विक्रम राव
जिस निर्लज्जता से केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश की अवमानना की है, वह अत्यंत गंभीर संवैधानिक गलती है।

केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 21 अक्टूबर, 2022 को राज्य शासन द्वारा नामित एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर डॉ. एम. एस. राजश्री की नियुक्ति को अवैध करार दिया था। न्यायाधीश-द्वय मुकेश कुमार रसिकभाई शाह तथा चुडलाटी थेवन रवि कुमार ने अपने आदेश में कहा कि केरल शासन का निर्णय त्रुटिपूर्ण है, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मान्य नियमों का उल्लंघन करता है। आयोग के अनुसार कुलपति के चयन के लिए खोज समिति बनती है जो कुछ नामों को अग्रसारित करती है। मगर डॉ. राजश्री का अकेला नाम सूची में था। वैकल्पिक नामांकन नहीं था। अतः वह रद्द कर दिया गया।

मगर माकपा शासन ने इस आदेश को क्रियान्वित नहीं किया। इसी तरह केरल उच्च न्यायालय ने

केरल मत्स्य पालन एवं महासागर अध्‍ययन विश्वविद्यालय (केयूएफओएस) के कुलपति की नियुक्ति को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उनकी नियुक्ति भी यूजीसी के मानदंडों के खिलाफ है। मुख्य न्यायाधीश एस. मणिकुमार और शाजी पाल चाली की खंड पीठ ने कहा कि डॉ. के. रीजि जॉन को केयूएफओएस का कुलपति नियुक्त करने के दौरान यूजीसी के उस नियम का पालन नहीं किया गया जिसके तहत कुलाधिपति को तीन या उससे अधिक दावेदारों की सूची भेजना अनिवार्य है। पीठ ने कहा कि नये कुलपति के लिए कुलाधिपति एक चयन कमेटी गठित कर सकते हैं। स्पष्ट किया कि कुलपति के चयन में यूजीसी के मानदंडों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय का यह फैसला डॉ. जॉन की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आया है।

यह फैसला राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा जॉन का इस्तीफा मांगे जाने के कदम को जायज ठहराता है। खान ने इस आधार पर जॉन का इस्तीफा मांगा था कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसे

ही एक मामले में कहा था कि यूजीसी के मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा गठित चयन कमेटी को कम से कम तीन उपयुक्त दावेदारों के नामों की सिफारिश करनी चाहिए थी। राज्यपाल चाहते हैं कि कुलपति का नामांकन आयोग की नियमावली के मुताबिक हो। पिनरायी विजयन अपने चहेतों को पदासीन कराना चाहते हैं। यही मूलभूत मसला है कि शासन नियमों पर चलेंगा या पार्टी हित में ? आरिफ मोहम्मद खान के विरुद्ध अभियान की वजह क्या है ? मुख्यमंत्री विजयन के निजी सचिव हैं केके रागेश। उनकी पत्नी को कन्नूर विश्वविद्यालय कुलपति तथा गोपीनाथ रवीन्द्रन को मलयालम भाषा विभाग में एसो. प्रोफेसर नियुक्त कर दिया गया है। चयन समिति के समक्ष छह प्रत्याशी पेश हुए थे।

सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के अनुसार डॉ. प्रिया का शोध स्कोर मात्र 156 था। द्वितीय स्थान पर नामित हुए प्रत्याशी को 651 अंक मिले थे। इंटरव्यू में द्वितीय आए उम्मीदवार को कुल 50 में से 32 अंक मिले जबकि प्रिया को पचास में से मात्र

विशेषज्ञों ने ईरान पर चीन के बढ़ते प्रभाव से निरूपित किया। उनका कहना है कि चीन ने चुपचाप काम करते हुए उन्हें एक बेहतर सौदे की पेशकश की। सितंबर, 2019 के बाद से तुर्किये ने चीन के प्रमुख सहयोगी पाकिस्तान और मलयेशिया के साथ मिलकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को रद्द करने के भारत के फैसले की निंदा की है।

भारत ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के मौके पर अंकारा के क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों के साथ कूटनीतिक रूप से बातचीत करके तुर्किये से नौसैनिक जहाजों की खरीद के लिए 232 करोड़ डॉलर के अनुबंध को रद्द कर दिया था और तुर्किये के प्रतिद्वंद्वी आर्मीनिया को सैन्य रडार के साथ आपूर्ति करने के लिए चार करोड़ डॉलर की बोली हासिल की थी। जैसा कि अमेरिका के अनुभव से पता चलता है, नई दिल्ली को पश्चिम एशिया में चीन के साथ अपने व्यापक टकराव में इच्छुक भागीदारों को खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

उनके शीर्ष सुरक्षा साझेदार होने के बावजूद वाशिंगटन ने इसाइल और खाड़ी राजशाही को चीन से दूर रहने से रोकने के लिए संघर्ष किया है, जिसे वे निवेश, प्रौद्योगिकी और हथियारों के क्षेत्रों में एक आकर्षक भागीदार के रूप में देखते हैं। यद्यपि भारत के इसाइल और खाड़ी राजतंत्रों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं- और 2014 में मोदी के पदभार संभालने के बाद से संबंधों में काफी सुधार हुआ है -यह चीन के साथ अधिक सहयोग के लिए उनकी भूख को रोकने में अमेरिका की तुलना में अधिक सफल साबित होने की संभावना नहीं है।

सहजीवन के संबंधों में असुरक्षा

मोनिका शर्मा
आज की जीवन-शैली में अपनाए जा रहे मनचाहे रिश्तों ने नई तरह की असामाजिकता, असुरक्षा और अपराध के आंकड़े बढ़ाए हैं। राजधानी दिल्ली में मुंबई की एक लड़की के साथ हुआ वीभत्स अपराध इसी की बानगी है। दिलि दहलाने वाली इस घटना में लंबे समय तक साथ रहने के बाद पीड़िता द्वारा शादी के लिए दबाव बनाने पर लिव-इन पार्टनर ने अपनी 26 वर्षीय साथी को न

केवल बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी, बल्कि उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर जंगल में फेंक दिया। बेटी का फोन नंबर बंद रहने और उसकी कोई खबर न मिलने पर पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई, तो हत्या के पांच महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ।

यह कटु सच है कि लिव-इन संबंधों में आए दिन घरेलू हिंसा, मौखिक दुर्व्यवहार और बर्बरता से हत्या के मामले सामने आते हैं।

हाल ही में जोधपुर में भी लिव-इन में रह रहे साथी को नशा करने

पर रोकने-टोकने के चलते पार्टनर ने गुस्से में गला दबाकर लड़की की जान ले ली थी। कुछ दिन पहले दिल्ली में ही एक और महिला की लिव-इन पार्टनर द्वारा हत्या कर लाश को हाड़वे पर फेंकने की घटना सामने आई। पिछले महीने मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लिव-इन रह रही महिला ने साथ रहने से मना किया, तो पार्टनर ने पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। ऐसी

घटनाओं के समाचार देश के कोने-

कोने से आते रहते हैं।

मौजूदा दौर में लिव-इन रिश्तेशनशिप से उपजी असुरक्षा इतनी बढ़ गई है कि कई बार न्यायालय द्वारा भी ऐसे रिश्तों पर तीखी टि्खपणी की गई है। बीते दिनों यौन उत्पीड़न के मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने लिव-इन संबंधों को अभिशाप बताते हुए उसे नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की

महिला का मनोबल

इसके चलते महिला सैनिकों को खासकर युद्धक विमान उड़ाने का अवसर मिला और अब वे ऐसा कर पा रही हैं। इसी क्रम में बतौस सेवानिवृत्त अल्पावधि सेवा यानी शार्ट सर्विस कमीशन के तहत चयनित महिला अधिकारियों को पेंशन देने की सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश से निस्संदेह उनका मनोबल बढ़ा है। सेना में दो तरह के अधिकारियों की भर्ती होती है।

एक तो वे होते हैं, जो सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवाएं देते हैं, दूसरे वे होते हैं, जो स्वेच्छा से अल्पावधि के लिए सेना में सेवा देने के लिए जाते हैं। अल्पावधि के लिए चयन और प्रशिक्षण आदि की प्रक्रिया लगभग वही होती है, जो स्थायी सेवाओं के लिए चुने जाने वाले अधिकारियों की होती है। मगर उनके वेतन और भत्तों से संबंधित नियम अलग होते हैं।

हालांकि अल्पावधि के अधिकारियों को स्थायी सेवाओं में बहाली का भी प्रावधान होता है, पर इसका निर्धारण संबंधित प्राधिकार करता है। अल्पावधि सेवाओं से निवृत्त हुए अधिकारियों के लिए दूसरे सरकारी महकमों की नौकरियों में कुछ आरक्षण होता है, पर जो सेना से मुक्त होने के बाद कहीं और चयनित नहीं हो पाते या जाना ही नहीं चाहते, उनके सामने नियमित आय की समस्या पैदा हो जाती है।

खासकर महिला सेनाधिकारियों के सामने यह समस्या अधिक जटिल हो जाती है, जब वे सेवामुक्त होकर कहीं और काम नहीं करतीं या कर पातीं। ऐसे में सेना से पेंशन उनके लिए बड़ा सहारा हो सकती है। इसी संबंध में अल्पावधि सेवा की बतौस महिला अधिकारियों ने सर्वोच्च न्यायालय के सामने पेंशन और स्थायी सेवा में बहाली के लिए गुहार लगाई थी।

हालांकि अदालत ने उनकी बहाली का आदेश तो नहीं दिया, पर सेना के अधिकारियों और सरकार से सिफारिश अवश्य की है कि उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए पेंशन बहाल की जाए। जिस मानवीय कोण से अदालत ने सिफारिश की और वायुसेना की तारीफ की, उससे उम्मीद बनी है कि इन महिला अधिकारियों के पक्ष में सकारात्मक रुख अपनाया जाएगा। दरअसल, सेना के मामले में नागरिक अदालतें कोई फैसला देने से बचती हैं। इसलिए कि सेना की अपनी अदालत ही सैनिकों और अधिकारियों से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान में प्राप्त अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले की सुनवाई की।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस समय भारतीय सेना को योग्य अधिकारियों की बहुत जरूरत है, मगर इस आधार पर नियम के अनुसार निवृत्त हुए अधिकारियों को सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता। फिर भी अगर किसी अधिकारी में जब्बा है, वह योग्य भी है और अल्पावधि से स्थायी सेवा में जाना चाहता है, तो उसके प्रति कुछ लचीला रुख अपनाने में कोई हर्ज नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसी बिंदु की तरफ इशारा किया है। फिर महिला अधिकारियों के मामले में मानवीय दृष्टि भी अपनाई जानी चाहिए। खासकर वायु सेना के अधिकारियों को तैयार करने में खासा वक्त और पैसा खर्च होता है। अगर अल्पावधि सेवा के लिए तैयार महिला अधिकारियों को सेवा विस्तार दिया जाता है, तो इससे दोनों की बचत होगी। अगर सेवा विस्तार संभव नहीं है, तो उनके भरण-पोषण के लिए नियमानुसार पेंशन की बहाली होनी ही चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का ताजा फैसला ऐसी अल्पावधि की अन्य महिला अधिकारियों के मामले में भी नज़ीर साबित होगा।

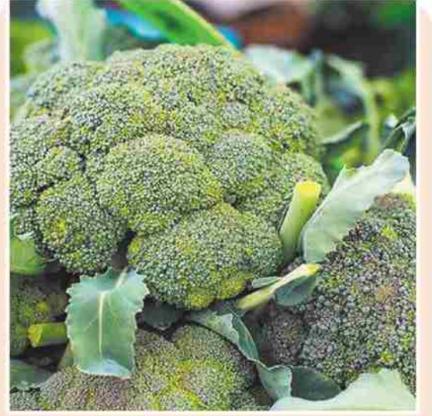
सांविधानिक गारंटी का बाई-प्रोडक्ट बताया था। दरअसल, लिव-इन रिश्तों में असुरक्षा और अपूर्णता हमेशा से बनी हुई है। एक-दूसरे का साथ पाकर भी सहजीवन के रिश्ते में भीतर के खालीपन और भय का माहौल हमेशा बना रहता है।

ऐसे अधिकतर रिश्तों का कोई भविष्य नहीं होता। कुछ समय पहले ऑरेंमेक्स मॉडिया द्वारा भारत के 40 शहरों में युवाओं को लेकर किए गए एक अध्ययन में 72 फीसदी युवाओं ने माना कि लिव-इन रि्लेशनशिप विफल रहते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से भी सहजीवन के रिश्ते में भावनात्मक धरातल पर रिक्तता ही देखने को मिलती है। ऐसी बर्बर घटनाएं ऐसे ही रीतेपन का नतीजा हैं। यही वजह है कि कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने लिव-इन रि्लेशनशिप को शादी का दर्जा देने की बात कही थी, ताकि सामाजिक और पारिवारिक ताने-बाने से दूर कानूनी नियमों के जरिये ही सही इन संबंधों को स्थिरता और सुरक्षा दी जा सके।

आज के युवा-युवतियों के लिए यह समझना जरूरी है कि बिना जवाबदेही वाले लिव-इन संबंधों में विवाह संस्था जैसी भावनात्मक, सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा मिल पाना मुश्किल ही है। ऐसा नहीं है कि शादी के रिश्ते में सब

हैं।

ब्रोकली की खेती कर किसान कमाएं अधिक मुनाफा



अनुमोदित किस्में

के.टी.एस - 1 :-

इस किस्म के शीर्ष हरे रंग के कोमल डंठल युक्त होते हैं, जिनका औसत वजन 200 - 300 ग्राम होता है और रोपाई के लगभग 80 - 90 दिनों बाद काटने योग्य हो जाता है। मुख्य शीर्ष काटने के कुछ दिनों बाद छोटे - छोटे शीर्ष शाखाओं की तरह मुख्य भाग के रूप में पत्तियों के कक्षों से निकलते हैं उन्हें भी काटकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

पालक समृद्धि

यह किस्म भी हरे शीर्ष वाली स्प्राउटिंग ब्रोकली किस्म है। जिसका शीर्ष भाग बड़ा एवं लम्बे कोमल डंठल युक्त होता है। प्रत्येक शीर्ष का औसत वजन 25 - 300 ग्राम होता है। मुख्य शीर्ष को काटने के बाद छोटे - छोटे शीर्ष पत्तों के कक्षों से निकलते हैं। यह किस्म 85 - 90 दिनों में रोपाई के बाद कटाई योग्य हो जाती है। इसमें येलो आई रोग एवं बैक्टीरिया विकार के लिए प्रतिरोधिता पायी जाती है।

एन.एस - 50

यह मध्यम अवधि में तैयार होने वाली संकर किस्म है। इनके हेड गूठीले, समरूप एवं गुम्बदाकार होते हैं। यह किस्म केट आई से रहित है। इसके पौधे मूडरोमिल आसिता एवं काला सडन रोग के प्रति सहनशील है। इसका बीज नामधारी मार्क से बाजार में मिलता है।

ब्रोकली संकर - 1 :-

इसकी परिपक्वता रोपाई के 60 - 65 दिन बाद होती है। इसके शीर्ष हरे रंग के गूठीले होते हैं, जिसका औसत वजन 600 - 800 ग्राम होता है। इसके बीज राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

टी.डी.सी. - 6 :-

इसके शीर्ष हरे रंग के होते हैं, जिसका औसत वजन 600 - 800 ग्राम होता है। इसकी फसल रोपाई के 65 - 70 दिन बाद तैयार हो जाती है। इसकी बुवाई दर 300 - 350 ग्राम प्रति हैक्टियर अनुमोदित की गयी है। इस प्रजाति के बीज उत्तराखंड तराई बीज निगम, पतनगर द्वारा किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

वैमिलस थुरिजोवैसिस का 1.5 - 2.0 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

फसल की कटाई

ब्रोकली के शीर्ष की कटाई शीर्ष की कलियों के खुलने से पहले ही की जाती है। शीर्ष को 10 - 20 से.मी. तने (डंठल) के साथ काट लिया जाता है। इसके पश्चात् निचले पत्तों के कक्षों से नई कोपलें निकलती हैं जिनमें छोटे - छोटे शीर्ष बनते हैं। इन्हें भी समय - समय पर काट लेना चाहिए।

उपज

ब्रोकली की औसत उपज 150 - 200 कुन्तल प्रति हैक्टियर (3 - 4 कुन्तल प्रति नाली) है।



व्याधियों से बचाव के इए यह उपाय अपनयें।

ब्यारी में 5 ग्राम थायरम प्रति वर्गमीटर की दर से अच्छी प्रकार मिलाकर 5 - 7 सेमी. की दुरी पर 1.5 - 2 सेमी. गहरी कतारें निकालें। तत्पश्चात् कवकनाशी 10 ग्राम ड्राईकोडर्मा या एक ग्राम कार्बेन्डाजिम अथवा 2.5 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से शोथित बीज की बुवाई करें तथा जमने तक हल्की सिंचाई फव्वारे द्वारा करें। अधिक वर्ष से बचाव हेतु नर्सरी की ब्यारी को घासफूस की छपर अथवा पालीथीन शीट से ढकने का प्रबन्ध रखना चाहिए। बेमौसमी खेती हेतु पौधे पालीथीन अथवा पालिन्डनल के अन्दर तैयार करनी चाहिए। पालीथीन अथवा पालीन्डनल के अन्दर भी पौधशाला में जड़ों में तापमान आवश्यकता से कम होने पर पालीथीन से हीटर लगा दें। इससे बीजों का जमाव शीघ्र होने में मदद मिलेगी।

रोपाई

रोपाई हेतु 25 - 30 दिन की पौध उपयुक्त होती है। अतः पौध तैयार होने पर रोपाई शीघ्र करें। रोपाई से पूर्व नत्रजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस एवं पोटेश की पूरी मात्रा और 500 ग्राम थीमेट प्रति नाली की दर से खेत में छिड़क कर अच्छी तरह खेत तैयार कर लें। उसके बाद कतार से कतार की दुरी 45 - 50 सेमी. तथा पौध की दुरी 45 - 50 सेमी. रखते हुये रोपाई कर हल्की सिंचाई करें। यदि कुछ पौधे मर गये हों अथवा बढवार अच्छी न हो तो उनके स्थान पर नई पौधों को पुनः रोपाई एक हफ्ते के अन्दर कर दें। रोपाई के एक माह बाद शेष आधी नत्रजन मात्रा छिड़क कर पौधों के चारों तरफ मिट्टी चढायें।

खाद या उर्वरक

उर्वरकों का प्रयोग मुदा परीक्षण के आधार पर करना उपयुक्त रहता है। अच्छी उपज के लिए प्रति हैक्टियर 15 - 20 टन गोबर / कम्पोस्ट खाद, 100 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटेश का प्रयोग किया जाना अनुकूल होता है।

खरपतवार नियंत्रण

शुरू के डेढ़ से दो माह तक खेत से खरपतवार निकलते रहें जिससे पौधों की बढवार अच्छी हो सके। इसके लिए आवश्यकतानुसार दो से तीन निराई - गुड़ाई पर्याप्त होगी।

जड़ विगलन

इस रोग के कारण रोपाई के उपरान्त कुछ पौधों की बढवार रुकी हुई दिखायी

पड़ती है। पौधों को उखाड़कर देखने पर पता चलता है कि इनकी जड़ें गलकर केवल एक तार की तरह हो गई हैं। इसकी रोकथाम के लिए बीज उपचार आर्द्रगलन रोग जैसा करें, रोपाई के समय पौध को दावा के घोल में डुबोकर लगायें तथा रोग के लक्षण खेत में दिखाई देने पर कार्बेन्डाजिम का 0.1 प्रतिशत की दर (एक ग्राम / लीटर पानी) से घोल बनाकर पौधों की जड़ों के पास छिड़काव करें तथा उचित फसलचक्र भी अपनायें। कलि पर्णचित्री रोग व मृदुल आसिता :-

इस रोग के कारण पत्तियों पर काले या भूरे धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण हेतु मैकोजेव 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से पौधों में छिड़काव करें।

कीट नियंत्रण

माहू :- इस कीट के व्यक्त तथा शिशु दोनों ही मुलायम पत्तियों से रस चूसकर पौधों को हानि पहुंचाते हैं। पत्तियां पिली पद कर सूखने लगती हैं। प्रकोप अधिक होने पर गोभी के शीर्षों में भी माहू दिखायी पड़ते हैं। इसके नियंत्रण हेतु एंजेडरेकटीन 1 - 2 मिली. अथवा इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली. प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें।

गोभी की तितली

यह एक सफेद रंग की तितली है, जिसके पीले रंग के अंडे गुच्छे में पत्तियों के पिछली स्थ पर बहुतायत में दिखाई पड़ते हैं। अंडों से निकलने वाली शुरुआती अवस्था से ही पत्तियों को भरी मात्रा में क्षति पहुंचती है। इसके नियंत्रण हेतु सबसे अंडों को चुनकर नष्ट कर दें फिर नियंत्रण हेतु इंडोसल्फान 35 ई.सी. का 2 मिली. अथवा इंडोबेसाकार्ब 14.5 ई.सी. का 0.2 मिली. या

रोग नियंत्रण

इस फसल में बीमारियों का प्रकोप अधिक नहीं होता है किन्तु रोपाई के बाद कुछ कीटों एवं व्याधियों का प्रकोप हो सकता है।

आर्द्रपतन

पौध जमीन की स्थ से गलकर मरने लगती है। इसके उपचार एवं रोकथाम के लिए निम्न उपाय अपनाए जायें।

भूमि में जल निकास का उचित प्रबन्ध करें।

नर्सरी का स्थान ऊँची जगह पर चुने एवं हर वर्ष बदलते रहें।

कार्बेन्डाजिम एक ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार कर बुवाई करें अथवा जैविक विधि से बीज उपचार हेतु ट्राइकोडर्मा विरिडी (4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज) अथवा ट्राइकोडर्मा हरजियानम 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज अथवा 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा एवं 2.5 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर प्रति नाली की दर से पौधशाला की मिट्टी में मिलायें।

नर्सरी में बीज की घनी बुवाई न करें और बुवाई कतारों में करें।

पौधशाला को सौर्यकरण द्वारा निर्ज्विकरण करें।

बुवाई के 10 दिन बाद कार्बेन्डाजिम की 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर ब्यारियों को तर करें तथा पुः 15 - 20 दिन बाद इसी दावा के घोल से ब्यारी को टर करें।

ब्रोकली गोभीय वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत एक प्रमुख सब्जी है। यह एक पौष्टिक इटालियन गोभी है। जिसे मूलतः सलाद, सूप, व सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। ब्रोकली दो तरह की होती है - स्प्राउटिंग ब्रोकली एवं हेडिंग ब्रोकली। इसमें से स्प्राउटिंग ब्रोकली का प्रचलन अधिक है। हेडिंग ब्रोकली बिलकुल फूलगोभी की तरह होती है, इसका रंग हरा, पीला अथवा बैंगनी होता है। हरे रंग की किस्म ज्यादा लोकप्रिय है। इसमें विटामिन, खनिज लवण (कैल्शियम, फास्फोरस एवं लौह तत्व) प्रचुरता में पाये जाते हैं।

पौष्टिकता से भरपूर होने के कारण गर्भवती महिलाओं के लिए अधिक फायदेमंद है। देश के बड़े शहरों में इसकी अत्यधिक मांग होने के कारण इसकी खेती पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाने लगी है। उत्तराखंड में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका बाजार भाव अधिक होने के कारण किसानों को अधिक आय प्रदान कर सकती है। अधिक मुनाफा देने के कारण किसान समाधान इसकी जानकारी लेकर आया है।

खेत की तैयारियां

ब्रोकली के लिए दुमट अथवा बलुई - दुमट मिट्टी वाली भूमि सर्वोत्तम माँग जाती है। अधिक अम्लीय भूमि इसके लिए अच्छी नहीं होती है। भूरी मिट्टी एवं उपजाऊपन वाले खेत भी इसकी खेती हेतु उपयुक्त होते हैं, किन्तु उनमें जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए अन्यथा पौधों की बढवार रुक जाती है और पौधे पीले पड़कर सड़ने लग जाते हैं। खेत की तैयारी के लिए दो जुताई पर्याप्त होती हैं, जिसमें अच्छी साड़ी गोबर की खाद दो कुन्तल प्रति नाली की दर से मिलाकर रोपाई हेतु पली - भति तैयार करना चाहिए।



बीज बुवाई का समय

अच्छे शीर्षों के निकलने एवं विकास के लिए 12 - 16 डिग्री सेन्टीग्रेट तापमान उपयुक्त होता है। अतः बीज की बुवाई एवं रोपाई के समय का निर्धारण उचित तापमान तथा क्षेत्र विशेषकर एवं वातावरणीय प्रस्थिति को ध्यान में रखते हुये किया जाना चाहिए।

निचले पर्वतीय क्षेत्र - सितम्बर अन्त से अक्टूबर मध्य पर्वतीय क्षेत्र - मध्य अगत से सितम्बर नैमीसमी खेती हेतु नवम्बर से मध्य जनवरी ऊँचे पर्वतीय क्षेत्र - मार्च अथवा अप्रैल

बीज दर

ब्रोकली के लिए 400 - 500 ग्राम बीज प्रति हैक्टियर (8 - 10 ग्राम प्रति नाली) पर्याप्त होता है।

पौधशाला की तैयारी

जमीन से 15 सेमी. उठी हुयी नर्सरी की ब्यारी में अच्छी साड़ी हुयी गोबर / कम्पोस्ट खाद तथा 50 - 60 ग्राम प्रति वर्गमीटर की दर से सिंगल सुपर फास्फेट मिलाकर भूमि की तैयारी करनी चाहिए। पौधशाला में भूमिगत कीटों एवं

चीकू की खेती भारत के आंध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु राज्यों में की जाती है। हाल के वर्षों में इसकी खेती अलग - अलग राज्यों में होने लगी है। इसकी खेती में कम लागत में अधिक मुनाफे के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रही है। इस फल के लिए एक खास बात यह है की इसकी खेती के लिए कम सिंचाई के साथ - साथ रख - रखाव आसान है। सबसे बड़ी बात है की इसकी अधिक मांग रहने से बाजार आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेकिन उन्नत तरह से खेती करने से चीकू का उत्पादन अधिक होता है।

चीकू की आधुनिक खेती कैसे करें?



पौध प्रवर्धन

चीकू की पौध बीज तथा कलम, भेंट कलम से तैयार की जाती है लेकिन व्यवसायिक खेती के लिए किसान को शीर्ष कलम, तथा भेंट कलम विधि द्वारा तैयार पौधों को ही बोना चाहिए। पौध तैयार करने की सबसे उपयुक्त समय मार्च - अप्रैल है।

पौधों की रोपाई

पौधों की रोपाई वर्ष ऋतु में उपयुक्त रहती है। पौधों की रोपाई

उन्नत किस्में

बड़े फल तथा पतले छिलके के साथ गुदा मीठा अच्छे चीकू का पहचान है इसलिए इसकी उन्नत किस्मों का अधिक ध्यान रखना जरूरी है। चीकू की उन्नत किस्में क्रिकेट बाल, कलि पत्ती, भूरी पत्ती, पी.के.एम.1, डीएसएच - 2 झूमकिया, आदि किस्में अति उपयुक्त है। क्रिकेट की बाल, कालीपट्टी, कलकत्ता राउंड, कीर्तिभारती, द्वारापुडी, पाला, पीकेएम -1, जोनाबालासा हू और डूडू, बैंगलोर, वावी बलसा आदि परन्तु उत्तरभारत में बारहमासी किस्म ज्यादा फेमस है।

से पहले पौधों के लिए जड़ों को तैयार जरूर कर लेना चाहिए। इसके लिए गर्मी के दिनों में ही 7 - 8 मी. दुरी वर्गाकार विधि से 90 से.मी. गहरा आकार के गड्ढे तैयार कर लेना चाहिए। गड्ढों को भरते समय मिट्टी के साथ लगभग 30 किलोग्राम गोबर की अच्छी तरह सड़ी खाद, 2 किलोग्राम करंज की खली एवं 5 - 7 कि.ग्रा. हड्डी का चुरा प्रत्येक गद्दे में डालकर भर देना चाहिए। पौधों को बोने के बाद जड़ों में मिट्टी भरकर थाला बना लें।

खाद एवं उर्वरक का उपयोग

पेड़ों में समय - समय पर खाद देते रहना चाहिए, जिससे पौधों का विकास 10 वर्षों तक होता रहे। पौधों के रोपाई के एक वर्ष बाद 4 - 5 टोकरी गोबर की खाद, 2 - 3 कि.ग्रा. अरण्डी / करंज की खली एवं 50:25:25 ग्रा. एन.पी.के. प्रति वर्ष डालते रहना चाहिए। यह मात्रा 10 वर्ष तक बढ़ाते रहना चाहिए तत्पश्चात् 500:250:250 ग्रा. एन.पी.के. की मात्रा प्रत्येक वर्ष देना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए की खाद और उर्वरक का उपयोग केवल जून तथा जुलाई में ही करना चाहिए। खाद सीधे जड़ में नहीं डालें बल्कि इसके लिए पौधे से दूर एक नाली बना लें उस नाली से खाद का घोल बनाकर दें।

सिंचाई

बरसात के मौसम में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन गर्मी के मौसम में 7 दिन पर तथा सर्दी के मौसम में 15

दिन पर सिंचाई करने से पौधों में फल तथा फूल अच्छे लगते हैं।

पौधों की देख रेख तथा काट छांट

चीकू के पौधों को विशेष रूप से सर्दी के मौसम में पाले से बचना जरूरी रहता है। यह खास ध्यान पौधों की रोपाई के 3 वर्ष तक रखने की जरूरत है। इसके लिए छोटे पौधों को बचाने के लिए पुआल या घास के छपर से इस प्रकार ढक दिया जाता है कि वे तीन तरफ से ढके रहते हैं और दक्षिण - पूर्व दिशा धूप एवं प्रकाश के लिए खुली रहती है। पौधों की रोपाई के समय मूल वृत्त पर निकली हुई टहनियों को काटकर साफ कर देना चाहिए। पेड़ का क्षत्रक भूमि से 1 मी. ऊँचाई पर बनने देना चाहिए। जब पेड़ बड़ा हो जाता है, तब उसकी निचली शाखायें झुकती चली जाती है और अन्त में भूमि को चुने लगती है तथा पेड़ की ऊपर की शाखाओं से ढक जाती है। इस शाखाओं में फल लगने भी बंद हो जाते हैं। इस अवस्था में इन शाखाओं को छीलकर निकाल देना चाहिए।

पुष्पन एवं फलन

शीर्ष कलम तथा भेंट कलम के द्वारा तैयार पौधों में 2 वर्षों के बाद फूल एवं फल आना आरम्भ हो जाता है। इसमें फल साल में 2 बार आते हैं। पहली फरवरी से जून तक और दूसरा सितम्बर से ऑक्टोबर तक। फूल लगने से लेकर फल पककर तैयार होने में लगभग चार महीने लग जाते हैं। चीकू के पौधों से

फल को गिरने से रोकने के लिए फूल के समय जिबरेलिक अम्ल के 50 से 100 पी.पी.एम. अथवा फल लगने के तुरंत बाद प्लैनोंफिक्स 4 मिली./ली. पानी के घोल का छिड़काव करने से फलन में वृद्धि एवं फल गिरने में कमी आती है।

रोग एवं कीट नियंत्रण

चीकू की पौधों में एक विशेषता यह रहती है की इस पर रोगों तथा कीटों का प्रकोप कम होता है। इसके बावजूद भी पर्ण दाग रोग तथा कलि बेधक, तना बेधक, पत्ती लपेटक एवं मिलीबग आदि कीटों का प्रभाव देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए मैकोजेव 2 ग्रा./ लीटर तथा मोनोक्रोटोफास 1.5 मिली./लीटर के घोल का छिड़काव करना चाहिए।

उपज

चीकू में रोपाई के दो वर्ष फल मिलना प्रारम्भ हो जाता है। जैसे - जैसे पौधा पुराना होता जाता है। उपज में वृद्धि होती जाती है। एक 30 वर्ष पेड़ से 25,00 से 3,000 तक फल प्रति वर्ष हो जाते हैं।



मंत्री शर्मा ने निर्माण श्रमिकों के हित में जिम्मेदारी से कार्य करने का किया आग्रह



अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 18 नवम्बर। राज्य के श्रम विभाग ने आज विभागीय मंत्री लोकनाथ शर्मा की अध्यक्षता में स्टेट एडवाइजरी कमिटी और सिक्किम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के प्रतिभागियों के साथ दो महत्वपूर्ण बैठकें कीं। स्थानीय श्रम भवन में आयोजित हुई इन बैठकों में सिक्किम विधानसभा के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में विधायक आदित्य गोले विशेष तौर पर शामिल हुए। उनके अलावा बैठक में श्रम सचिव कर्मा नामग्याल भूटिया, पीसीई सह सड़क व सेतु सचिव टीपी सांदरपा, पीसीई सह भवन व आवास सचिव प्रवीण कुमार प्रधान, विशेष श्रम आयुक्त डीएस कुंवर, तीस्ता ऊर्जा उप प्रबंधक जिग्मी सी भूटिया, एनएचपीसी के सीनियर एचआर अभिषेक कुमार के अलावा समिति

सदस्यों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया।

सिक्किम बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर की बैठक के दौरान मंत्री शर्मा ने श्रमिक कल्याण सम्बंधित विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा के बाद पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने और मजदूरों के कल्याण हेतु व्यापक रूप से उत्पादनोन्मुखी प्रैक्टिस सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि समिति ने श्रमिकों को कुशल बनाकर उनके रोजगार में सहायता हेतु प्रमाणपत्र प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सभी जिलों में बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी बात की और मजदूरों के हित के लिए सभी सम्बंधित विभागों से सक्रिय सहयोग और हस्तक्षेप का आग्रह किया।

इसके बाद राज्य सलाहकार

समिति की बैठक हुई जिसमें वित्त निदेशक लिनस राई, राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के अलावा ग्रेफ 129 आरसीसी के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसमें निर्माण स्थलों पर श्रम कानूनों के सम्बंध में जागरूकता शिविर लगाने, वाहनों की खरीद एवं पुनर्संशोधन, कोविड राहत राशि एवं अन्य कल्याणकारी सामग्रियों के वितरण, बीओसीडीब्ल्यू छात्रावास के जीर्णोद्धार, जिला श्रम कार्यालयों के मजबूतीकरण और अन्य सम्बंधित विषयों पर चर्चा की गयी। इस दौरान मंत्री शर्मा ने बोर्ड को सम्बोधित करते हुए सभी सदस्यों से मजदूरों के कल्याण हेतु अपनी जिम्मेदारियों का भली-भांति निर्वहन करने का आग्रह किया।

गुजरात में बीजेपी ने दी है दंगा मुक्त और सुशासन युक्त सरकार : अनुराग ठाकुर

सूरत, 18 नवम्बर (एजेन्सी)। केंद्रीय सूचना प्रसारण तथा खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुजरात में दंगा मुक्त और सुशासन युक्त सरकार देने की बात कहते हुए यह दावा किया है कि गुजरात में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है और गुजरात की प्रचंड जीत के साथ ही 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल भी फूँका जाएगा।

शुक्रवार को गुजरात के सूरत जिले की चार विधानसभा सीटों-मंगरोल, मांडवी, बारडोली और सूरत पश्चिम जनसभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने अपने राज में गुजरात को दंगों वाला राज्य बना दिया था। कांग्रेस के शासनकाल में साम्प्रदायिक दंगे, गैंगस्टर और गैंगवार से गुजरात की पहचान होने

लगी थी जिस पहचान से गुजरात की जनता को मुक्ति दिलाने का काम भाजपा सरकार ने किया है।

ठाकुर ने कहा कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दंगा मुक्त एवं सुशासन युक्त सरकार देने का काम किया है। यह बात हमें नहीं भूलनी है कि गुजरात का विकास सिर्फ एक राज्य का विकास नहीं है। इस विकास के साथ हमारे देश का विकास भी जुड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गुजरात मेरी आत्मा है और भारत मेरा परमात्मा।

गुजरात और पीएम मोदी के अटूट रिश्ते पर बोलते हुए ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बावजूद मोदी ने पिछले आठ सालों में कभी गुजरात से अपने रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने दिया। आज पूरा देश

गुजरात को मोदी का गुजरात कहता है। यह गुजरात मोदी ने बनाया है। इस बात को विपक्ष की पार्टियां भी मानने को मजबूर हैं। इसलिए वे जब मोदी को बदनाम करते करते थक जाती हैं तो वे गुजरात और गुजरातियों को बदनाम करने की साजिश में लग जाती हैं।

हाल ही में राहुल गांधी द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान की भत्सर्ना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी 'टुकड़े टुकड़े गैंग' के साथ भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वो हिंदू आतंकवाद के बारे में बातें करते हैं, जेएनयू में भारत को तोड़ने की साजिश करने वालों के साथ खड़े रहे और अब वो वीर सावरकर पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। ये कांग्रेस की दोगली चाल है, वो एक परिवार से आगे कुछ नहीं



देख पा रहे हैं। कांग्रेसी नहीं जानते कि गुजरात का मॉडल विकास का नंबर 1 मॉडल है। गुजरात की गली गली में भाजपा की गूँज है। कांग्रेस सिर्फ टोपियों की राजनीति करती है। विकास पर कभी बात नहीं करती है।

गुजरात में प्रचंड जीत का दावा करते हुए ठाकुर ने आगे कहा कि गुजरात के विधानसभा चुनावों में हम इतनी प्रचंड जीत लेकर आये

कि 2024 के लोकसभा चुनावों का बिगुल इसी जीत के साथ फूँका जायेगा। गुजरात ने देश को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री और पशु पालन मंत्री दिये हैं तो ऐसे में गुजरात से भारतीय जनता पार्टी को भारी जीत मिलनी चाहिए ताकि पूरे देश में संदेश जाये कि आखिर डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है?

प्रदेश भाजपा को नवनिर्वाचित पंचायतों से राज्य की बेहतर हेतु कार्य करने की उम्मीद

अनुगामिनी का.सं.

गंगटोक, 18 नवम्बर। सिक्किम प्रदेश भाजपा ने हाल ही सम्पन्न हुए राज्य पंचायत चुनाव के सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों, जिलाध्यक्षों एवं उपाध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना करते हुए इस निर्दलीय चुनाव को राज्य के हित में महत्वपूर्ण बताते हुए सभी से राज्यवासियों की बेहतर हेतु कार्य करने का आह्वान किया है।

प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष डीबी चौहान ने आज एक विज्ञप्ति के माध्यम से कहा कि 10 नवम्बर को सम्पन्न हुए द्विस्तरीय सिक्किम पंचायत चुनाव के नतीजों के साथ ही सभी जिलों में जिलाध्यक्षों और उपाध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। इस बार के निर्दलीय पंचायत चुनाव में विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के लोगों ने भी खुलकर हिस्सा लिया और अपना दबदबा कायम किया है।

चौहान ने आगे कहा कि भारतीय संविधान में पंचायती राज स्थानीय स्वराज या स्थानीय सरकार के रूप में प्रतिष्ठित है, जिसके पास अपने गांव-समाज के आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय की मजबूती के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं को हर घर तक प्रभावी



दंग से पहुंचाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा, इस पंचायत चुनाव में निर्दल प्रार्थी बन कर अपने गांव-समाज के विकास हेतु बड़ी संख्या में गैर-राजनीतिक हस्तियां भी आगे आई हैं। लंबे समय से राजनीतिक रूप से सक्रिय पंचायत व्यवस्था को स्वच्छ व निष्पक्ष बनाने में इन स्वतंत्र निकायों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में प्रदेश की जनता को लंबे राजनीतिक भेदभाव के कारण सरकारी सुविधाओं से वंचित तबके को स्वतंत्र पंचायत व्यवस्था से उचित न्याय मिलने की उम्मीद है।

इसके साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित पंचायतों से अगले पांच वर्षों तक सिक्किम के लोगों एवं समाज की आशाओं और आकांक्षाओं को सर्वोपरि रखते हुए काम करने की कामना की है।



राष्ट्र का हरित विद्युत

के साथ सशक्तिकरण
अवसंरचना संवर्धन
बदलता अरुणाचल प्रदेश



अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित
600 मेगावाट कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का

परियोजना के परिणाम और लाभ

- पूर्वोत्तर में 3353 मिलियन यूनिट बिजली के वार्षिक उत्पादन के साथ सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन शुरू किया गया
- अरुणाचल प्रदेश को सालाना 402 मिलियन यूनिट अनुमानित मुफ्त विद्युत प्रदान की जाती है जो राजस्व के मामले में 161 करोड़ रुपये के बराबर है
- पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड और उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ को विद्युत की आपूर्ति की जाती है
- यह 70 मीटर और 24.5 मीटर ऊंचाई के दो कंक्रीट ग्रेविटी बांधों के साथ भारत में निर्मित सबसे जटिल हाइड्रोलिक संरचनाओं में से एक है
- लगभग 100 किमी ट्रांसमिशन लाइन और 4 सबस्टेशनों का निर्माण किया
- ग्रिड में सौर और पवन ऊर्जा के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
- मत्स्य पालन और पर्यटन की संभावना वाले बिचोम और टेंगा बांधों के पीछे जलाशय बनाए गए
- 38.56 करोड़ रुपये की लागत से सभी सुविधाओं से युक्त दो आदर्श गांव बनाए और 80 किलोमीटर से अधिक संयंत्र पहुँच मार्ग का निर्माण किया

श्री नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री
द्वारा
राष्ट्र को समर्पण

गरिमापूर्ण उपस्थिति

त्रिगेडियर (डॉ.) बी.डी. मिश्रा (सेवानिवृत्त) राज्यपाल, अरुणाचल प्रदेश	श्री पेमा खांडू मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश	श्री किरेन रिजिजू केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री	श्री चोवना मेन उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश	श्री नबाम रेबिआ सांसद (राज्यसभा)
--	--	---	--	--

शनिवार, 19 नवंबर, 2022 | प्रातः 9.30 बजे | डोनी पोलो हवाईअड्डा, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश

इस इवेंट को डीडी न्यूज पर लाइव देखें



डियर साप्ताहिक लॉटरी मुम्बई की एक गृहिणी ने ₹1 करोड़ जीते



मुम्बई, महाराष्ट्र की श्रीमती नीतु संकेत सोनी ने 30.09.2022 को

सम्पन्न हुए डियर साप्ताहिक लॉटरी के ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के तौर पर रु. 1 करोड़ जीते हैं। उनकी विजेता टिकट का नम्बर 87B 64111 है। 'जब मुझे डियर लॉटरी से पुरस्कार राशि के एक करोड़ रुपये जीतने की जानकारी हुई तो मुझे बेहद प्रसन्नता महसूस हुई। मेरी खुशियां भी असीमित एवं अनियंत्रित हैं। अपने पूरे जीवन भर में हमारे बैंक खाते में एक करोड़ की भारी-भरकम राशि देखना आसान नहीं है। लेकिन डियर लॉटरी के माध्यम से यह सम्भव हो गया है। इस आश्चर्यजनक अवसर के लिए मैं डियर लॉटरी के साथ ही नागालैंड स्टेट लॉटरीज के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। विजेता ने कहा।